

विहगावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2006 की गतिविधियाँ

1.1 वर्ष 2006 के दौरान 5.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऊँची वृद्धि जारी रही। यह लगातार चौथा वर्ष है जिसमें 2003¹ में शुरू हुई 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि बनाये रखी गयी। वैश्विक उत्पादन में व्यापक विस्तार की व्याख्या अमरीकी उपभोग में लचीलेपन के रूप में की जा सकती है। वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि में कुछ कमी आने के बावजूद यूरोप और जापान तथा अन्य उन्नत औद्योगिक देशों में व्यापक उछाल आया तथा उभर रही बाजार अर्थव्यवस्थाओं विशेषतः चीन (11.1 प्रतिशत), भारत (9.4 प्रतिशत) और रूस (6.7 प्रतिशत), में तीव्र वृद्धि जारी रही। वैश्विक उत्पादन में वृद्धि की अगुआई उभर रहे एशिया द्वारा की गई, जिसने 2006 में वैश्विक वृद्धि में 3.9 प्रतिशत का अंशदान किया जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने 1.5 प्रतिशत का अंशदान किया। 2002 से पहली बार यूरो क्षेत्र में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में संयुक्त राज्य में हुई वृद्धि से अधिक रही। वित्तीय संसाधन, मजबूत पण्य मूल्यों तथा प्रचुर वैश्विक चलनिधि की उपलब्धता के कारण उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में मजबूती बनी रही। तथापि, इनमें से कुछ कारणों के बने रहने के संबंध में चिंताएं बनी रहीं। 2006 के मध्य में जापान के आर्थिक कार्यकलाप में मंदी आयी परंतु उसमें वर्ष के अंत तक सुधार आया।

1.2 कई देशों में उत्पादन संभाव्यता के निकट रहा, तथापि सशक्त मांग और वैश्विक पण्य कीमतों में तेजी के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कुछ मुद्रास्फीतिक दबाव बना रहा। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति ने ऊर्जा मूल्यों का निकट से अनुसरण किया - जो वर्ष के अंत में ऊर्जा के मूल्य में गिरावट के साथ तेजी से गिरने के पहले तेल के भाव में बढ़त के साथ 2006 की प्रथम छमाही में 3 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। कैलेंडर वर्ष 2006 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक साल पहले जैसी थी, परंतु वह पिछले 5 वर्ष की अवधि (2000-04) के दौरान के 1.9 प्रतिशत से अधिक रही। 'विकासमान एशिया' में मुद्रास्फीति

2000-04 के 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 2005 में 3.6 प्रतिशत तथा 2006 में 4.0 प्रतिशत हो गयी।

1.3 प्रमुख देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति के लक्ष्य/सुखद सीमा पार करने के साथ, कई केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक सख्ती बरती। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड (यूएस फेड) यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्वेरिज्स रिक्स बैंक (स्वीडन) रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया और बैंक ऑफ जापान ने वर्ष के दौरान अपनी नीतियाँ सख्त बनायीं।

1.4 उन्नत औद्योगिक देशों में राजकोषीय शेष में 2006 में सुधार के संकेत मिले। संरचनागत बजट घाटे के उपाय, जो घाटा संबंधी प्रमुख आंकड़ों से चक्रिय प्रभाव को हटाने का प्रयास करते हैं, में संयुक्त राज्य (जीडीपी के 1 प्रतिशत अंक से अधिक), जर्मनी (0.8 प्रतिशत अंक तक) और जापान (मुख्यतः पूँजी अंतरणों में एक बार के परिवर्तनों के कारण 0.5 प्रतिशत अंक तक) की गिरावट आयी तथा सिर्फ इटली में उसमें सामान्य वृद्धि हुई। जर्मनी के हेडलाइन शेष में परिवर्तन अधिक स्पष्ट था तथा 2006 में इसमें घाटे में 1.8 प्रतिशत अंक तक गिरावट आयी।

1.5 जहाँ संयुक्त राज्य में ऋण की स्थितियाँ सख्त हो गयीं, वहीं कई अन्य क्षेत्रों में विस्तार जारी रहा। फलस्वरूप, वैश्विक आस्तित्व मूल्य या तो बढ़ते रहे अथवा उन्हें अस्वाभाविक रूप से ऊँचे स्तरों पर बनाये रखा गया। एशिया के कई उभर रही बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने उचित रूप से सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के साथ सशक्त वृद्धि दर्ज की तथा इसमें उनके निर्यात की सशक्त वैश्विक मांग, अनुकूल व्यापार शर्तों, बाह्य वित्तपोषण तक आसान पहुँच एवं विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की सुखद स्थिति तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लघुकृत बाह्य ऋण ने मदद की। सुधारे गये पुनर्विन्यास और पर्यवेक्षी प्रणालियों के जरिये उनकी बैंकिंग प्रणाली भी सशक्त की गयी है। बाहरी आघातों के प्रति लचीलापन को विनिमय दर जोखिमों के प्रति तुलनपत्र के कम एक्सपोजर, ऋण विन्यासों में पुनर्वित्तीयन के कम जोखिम, सशक्त वित्तीय प्रणाली तथा नीतिगत गुरुतर लचीलेपन से बल मिला है। फिर भी, चिंताजनक क्षेत्र हैं और इनमें से कई देशों ने

¹ इस अध्याय में वैश्विक विकास कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) से संबंधित है, जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किये जाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से संबंधित है।

निष्प्रभावीकरण सहित हस्तक्षेप के जरिये विदेशी मुद्रा बाजारों की अतिरिक्त अस्थिरता को रोकने की जरूरत महसूस की है। तथापि, इन नीतियों की अपनी सीमाएँ हैं और ऐसी कार्रवाई के साथ नकदी आरक्षित निधि अपेक्षाओं को बढ़ाने सहित चलनिधि प्रबंधन की अलग रणनीतियाँ, केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के निर्गम, विशिष्ट क्षेत्रों को उधार देने पर अधिकतम सीमा तथा विवेकपूर्ण साधनों का उपयोग शामिल हैं।

1.6 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में, 2006 के अधिकांश समय में तथा 2007 के प्रारंभ में जोखिमपूर्ण आस्तियों के भाव बढ़ते रहे। कई ईक्विटी बाजार ऐतिहासिक उँचाई पर पहुँच गए; जबकि विभिन्न ऋण अंतराल निचले स्तर तक आ गये। उन्नत औद्योगिक देशों में सरकारी बांडों की आय 2006 के मध्य के स्तर पर आ गयी और उसके बाद नीचे जाने लगी। विशेषतः संयुक्त राज्य में दीर्घावधि बांड की आय में वर्ष की दूसरी छमाही में नीचे जाने की प्रवृत्ति पायी गयी जो संयुक्त राज्य की वृद्धि की संभावनाओं के बारे में निवेशकों की चिंता को तथा नरम हो रही मौद्रिक नीति की प्रत्याशाओं को प्रतिबिंबित करती है। जापान में आर्थिक दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक रहा, जिसने बांड आय में कुछ समर्थन दिया, जबकि यूरो क्षेत्र के आर्थिक दृष्टिकोण में क्रमिक रूप से चमक आयी तथा अंततः यूरो बांड की आय में वृद्धि हुई। सतत सशक्त आय वृद्धि विकसित ईक्विटी और ऋण बाजारों में लाभ के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा, पूँजी संरचना में चल रहे परिवर्तनों ने शेयरों की पुनर्खरीद और बढ़ने तथा विलय और अर्जन कार्यक्रमों में पर्याप्त वृद्धि के साथ ईक्विटी बाजार को उछाला। इसी तरह, क्रेडिट रेटिंग में सुधार और सामान्यतः सशक्त समष्टि आर्थिक स्थितियों ने उभर रहे बाजारों को फायदा पहुँचाया।

1.7 उन्नत औद्योगिक देशों में वित्तीय फर्मों का सशक्त समग्र कार्यानिष्पादन इस वर्ष के दौरान जारी रहा तथा बैंकों को आम तौर पर अनुकूल ऋण वातावरण तथा सुदृढ़ खुदरा कारोबार वाले एक और वर्ष से फायदा मिला। निवेश बैंकों ने पूँजी बाजार कार्यक्रमों में वृद्धि तथा निजी ईक्विटी में उछाल के कारण रिकार्ड लाभ कमाया। निधियों द्वारा दर्ज की गयी प्रतिलाभ की गिरती दरों के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में बचाव निधियों में निवेशकों की आवक राशियाँ सामान्य रहीं। वर्तमान लाभ ने पहले से अच्छे पूँजी उपधानों में वृद्धि की है जिससे यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में संभावित दबावों को झेलने के लिए वित्तीय फर्म भलीभाँति तैयार हैं।

2007 की गतिविधियाँ

1.8 वैश्विक जीडीपी वृद्धि, जो 2006 में 5.4 प्रतिशत बढ़ गयी थी, ने 2007 की पहली छमाही में गति बनाये रखी तथा ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक तथा उभरते बाजार देशों में वह व्यापक

हो गया है। अक्टूबर 2007 में जारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 'वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण' के अनुसार विश्व के जीडीपी में वास्तविक वृद्धि 2006 में 5.4 प्रतिशत थी जो 2007 में गिरकर 5.2 प्रतिशत और 2008 में 4.8 प्रतिशत रह जाने की संभावना है। हालांकि संयुक्त राज्य में 2007 की पहली तिमाही में वृद्धि में कमी आयी, पर हाल के संकेतक यह बताते हैं कि दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में गति आयी है। कई अन्य देशों में कार्यकलाप का तेजी से बढ़ना जारी रहा। यूरो क्षेत्र और जापान में, वृद्धि प्रवृत्ति से ऊपर बनी रही तथा उसमें कुछ ऐसे शुभ संकेत थे कि विस्तार में घरेलू मांग की अधिक केंद्रीय भूमिका है। उभरते बाजार वाले देशों का मुख्य रूप से बढ़ना जारी रहा तथा इसकी अगुआई चीन, भारत और रूस की त्वरित वृद्धि में देखी गयी।

1.9 यूएस में खाद्यान्नों तथा इंधन तथा यूरो क्षेत्र में शिक्षा तथा वस्त्र के मूल्यों में वृद्धि को प्रतिबिंबित करते हुए 2007 की तीसरी तिमाही की समाप्ति के आसपास प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति में सामान्यतः वृद्धि हुई। दूसरी ओर, आवास तथा घरेलू सेवाओं के नकारात्मक योगदान के चलते यूके में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी का रुख रहा। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, अक्टूबर 2007 में यूएस की हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.5 प्रतिशत, यूके की 2.1 प्रतिशत और यूरो क्षेत्र की 2.6 प्रतिशत थी। सितंबर 2007 में ओईसीडी देशों में मुद्रास्फीति की दर 2.2 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह दर 2.0 प्रतिशत थी। मांग की सुदृढ़ स्थिति को प्रतिबिंबित करते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मूल मुद्रास्फीति में वृद्धि का रुख रहा।

1.10 वैश्विक ऋण बाजारों में मई 2007 से बड़ी अस्थिरता आयी है क्योंकि यूएस 'सब-प्राइम' बंधक उधार से हानियों के आकार और वितरण के बारे में अनिश्चितताओं ने निवेशकों को अपनी स्थितियाँ समायोजित करने पर मजबूर किया। 2006 के उत्तरार्द्ध से, यूएस में 'सब प्राइम' बंधक बाजार क्षेत्र की स्थितियों में उल्लेखनीय गिरावट आयी है जिसके फलस्वरूप सारे उत्पादों एवं बाजारों के निवेशकों द्वारा जोखिम का पुनराकलन करना पड़ा। यद्यपि हानियाँ ज्यादातर यूएस में संकेन्द्रित थीं पर वे तेजी से आस्तिसमर्थित प्रतिभूतियों और संपाश्विकीकृत ऋण दायित्वों को धारित करनेवाले यूरोपीय और एशियाई निवेशकों तक तेजी से वितरित हो गयीं। एशिया के भीतर, एक्सपोजर जापान, चीन, चीन के ताइवान प्रांत, द.कोरिया और आस्ट्रेलिया में संकेन्द्रित होना सूचित किया गया।

1.11 कई अर्थव्यवस्थाओं में अल्पावधि दरों में और तेजी आ गयी तथा वे व्यापक तौर पर नीति दरों के अनुरूप चलती रहीं। मुद्रास्फीति रोकने और मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए सितंबर 2007 को समाप्त तिमाही के दौरान कई केंद्रीय

बैंकों यथा बैंक ऑफ इंग्लैंड, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने अपनी नीति दरों को और बढ़ा दिया। दूसरी ओर यूएस में अल्पावधि ब्याज दरों में गिरावट आयी जो 31 अक्टूबर 2007 को फेड निधियों की लक्ष्य दर में 75 आधार अंक की कटौती होकर उसके 4.50 प्रतिशत होने में प्रतिबिंबित हुई। जून 2004 से जून 2006 तक फेडरल रिजर्व द्वारा लगातार 17 बार दरों में की गयी वृद्धि तथा अगस्त 2007 में आये विराम के बाद 18 सितंबर 2007 में यूएस में पहली बार दरों में उक्त कटौती की गयी। कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील और थाईलैंड में अल्पावधि दरों में नरमी आयी क्योंकि इन देशों के केंद्रीय बैंक वृद्धि के समर्थन के लिए नीतिगत दरों में कटौती करते रहे।

1.12 अल्पावधि ब्याज दरों के विपरीत, सरकारी बांडों में दीर्घावधि आय 2007-08 की दूसरी तिमाही में प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नरम रही तथा इस तरह पहली तिमाही में बढ़त की प्रवृत्ति में बदलाव नजर आया। आवास बाजार में गिरावट तथा ऋण बाजार में उथल-पुथल की स्थिति में, बांड आय में आयी गिरावट ने जोखिमपूर्ण आस्तियों के लिए निवेशकों की कम चाहत को प्रतिबिंबित किया। मार्च 2007 के अंत और 19 नवंबर 2007 के बीच 10 वर्षीय प्राप्तियों में यूएस में 35 आधार अंकों की, जापान में 15 आधार अंकों की, यूके में 17 आधार अंकों की गिरावट आयी, जबकि यूरो क्षेत्र में 11 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

1.13 2007 की तीसरी तिमाही में वैश्विक ईक्विटी बाजारों में बीच-बीच के सुधारों के मध्य और वृद्धि दर्ज की गयी। कंपनी आय में वृद्धि, विलय और अर्जन कार्यकलापों में उछाल तथा जोखिम सहने की क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, यथा चीन (69.8 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (32.2 प्रतिशत), हांगकांग (30.7 प्रतिशत), ब्राजील (28.7 प्रतिशत), इंडोनेशिया (28.5 प्रतिशत), तुर्की (25.1 प्रतिशत) और थाईलैंड (21.3 प्रतिशत) में, ईक्विटी बाजारों में उछाल दिखायी दिया। तथापि, यूएस में आवास की बिक्री में मंदी तथा यूएस बंधक एवं कंपनी उधार बाजारों के बारे में बढ़ती हुई चिंता, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, चीन की मुद्रास्फीति दर में वृद्धि तथा जापान की अर्थव्यवस्था में संकुचन ने बीच-बीच में बाजार के रुख को मंद किया।

1.14 विदेशी मुद्रा बाजार में, 14 सितंबर 2007 तक अमरीकी डॉलर में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्यहास हुआ जो बंधक बाजार में चिंता, गिरती आवास बिक्री और कमजोर उपभोक्ता विश्वास में प्रतिबिंबित हुआ। पौंड स्टर्लिंग यूएस डॉलर की तुलना में मजबूत होकर जुलाई 2007 में 25 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया तथा येन के 'कैरी ट्रेड' में नरमी के फलस्वरूप यूएस डालर की तुलना में जापानी येन में मूल्यवृद्धि हुई।

भारतीय अर्थव्यवस्था

समष्टि वातावरण

1.15 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2006-07 के दौरान तेज वृद्धि दर्ज की। वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर पिछले साल के 9.0 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2006-07 में 9.4 प्रतिशत हो गयी, जिसमें मुख्यतः उद्योग एवं सेवाओं में निरंतर विस्तार का योगदान था। दसवीं योजनावधि (2002-03 और 2006-07) में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि औसतन 7.6 प्रतिशत थी - जो अब तक किसी भी योजनावधि की सर्वाधिक औसत वृद्धि दर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमान के अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से उत्पन्न वास्तविक जीडीपी ने पिछले वर्ष के 6.0 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 2.7 प्रतिशत की न्यूनतर वृद्धि दर्ज की। तथापि, उद्योग से हुई वास्तविक जीडीपी की वृद्धि के विस्तार का यह पांचवां साल था क्योंकि इसने वर्ष के दौरान 11.5 प्रतिशत (2005-06 में 8.2 प्रतिशत) की द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की, जो 1995-96 के बाद की सर्वाधिक वृद्धि थी। जहां औद्योगिक वृद्धि मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र का परिणाम थी, खनन और बिजली दोनों क्षेत्रों ने तीव्र वृद्धि दर्ज की। उपयोग आधारित वर्गीकरण के रूप में 18.2 प्रतिशत वृद्धि के साथ पूंजीगत माल क्षेत्र का कार्यनिष्पादन विशेष रूप से प्रभावी था। आधारभूत माल और उपभोक्ता माल क्षेत्र ने भी 2006-07 के दौरान 10.3 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत की द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की। अच्छी तरह से कार्य कर रहे औद्योगिक क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के सुधरे हुए कार्यनिष्पादन, 2006-07 में 8.8 प्रतिशत वृद्धि, से उछाल आया। सेवा क्षेत्र ने पिछले तीन वर्षों में लगातार द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की। इसने 2005-06 की 10.3 प्रतिशत वृद्धि के ऊपर 2006-07 में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो नयी शृंखला के अनुसार 1999-2000 से सर्वाधिक वृद्धि है।

1.16 कई उद्योगों में उच्चस्तरीय क्षमता उपयोग, प्राथमिक वस्तुओं से आपूर्ति आघात सहित, 2006-07 के दौरान मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित हुआ। थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष घटबढ़ द्वारा मापी गयी हेडलाइन मुद्रास्फीति 31 मार्च 2007 को 5.9 प्रतिशत बढ़ी - यह नवंबर 2006 के मध्य और मार्च 2007 के अंत के बीच रिजर्व बैंक के 5.0-5.5 प्रतिशत के संकेतक प्रक्षेपणों के ऊपरी छोर के ऊपर थी। 2006-07 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.7-6.7 प्रतिशत के दायरे में रही। औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति एक वर्ष पूर्व के 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 5.4 प्रतिशत हो गयी। प्रमुख समूहों में प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों ने 2006-07

के दौरान मुद्रास्फीति पर ऊपरी दबाव बनाया, जो प्रमुख कृषि फसलों की देशी आपूर्ति में कमी को दर्शाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति के परिणाम को प्रभावित करनेवाली ईंधन समूह की मुद्रास्फीति ने वर्ष की दूसरी छमाही में उल्लेखनीय नरमी दर्शायी और वह दशक की न्यूनतम दर तक पहुंच गयी। मुख्यतः उच्चतर खाद्य मूल्यों के प्रभाव को दर्शाते हुए उपभोक्ता मूल्य में मुद्रास्फीति के माप पूरे 2006-07 के दौरान थोक मूल्य मुद्रास्फीति के ऊपर रहे।

1.17 राजकोषीय स्थिति में चल रहा सुधार 2006-07 के संशोधित अनुमान बनाम बजट अनुमानों में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए प्रमुख घाटा संकेतकों के न्यूनतर अनुमानों में प्रतिबिंबित हुए। केंद्र सरकार का राजस्व घाटा रु. 80,410 करोड़ या जीडीपी का 1.9 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 2006-07 के बजट अनुमान में जीडीपी के 2.1 प्रतिशत तथा 2005-06 के 2.6 प्रतिशत से कम है। 2006-07 के लिए सकल राजकोषीय घाटा रु. 1,42,793 करोड़ था जो पिछले वर्ष में 3.8 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत के बजट अनुमानों की तुलना में जीडीपी का 3.5 प्रतिशत था। कर राजस्व में बने हुए उछाल तथा योजना व्यय में वृद्धि पर नियंत्रण के फलस्वरूप प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में सुधार हुआ। राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करते हुए केंद्र सरकार की बकाया देशी देयताएं मार्च 2006 के अंत के 63.4 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में जीडीपी का 61.5 प्रतिशत (सं.अ.) रह गयीं।

1.18 व्यापक मुद्रा (एम₃) में साल-दर-साल वृद्धि एक वर्ष पूर्व के 17.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 21.3 प्रतिशत हो गयी तथा वह अप्रैल 2006 में वार्षिक नीति विवरण में प्रक्षेपित 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर के ऊपर रही। तीसरे क्रमिक वर्ष में 2006-07 के दौरान वाणिज्यिक ऋण की मांग सुदृढ़ बनी रही, हालांकि उसमें कुछ नरमी आयी। वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण की वार्षिक वृद्धि 31 मार्च 2007 को 25.4 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पहले के 27.2 प्रतिशत से कम थी। सरकार को वाणिज्यिक बैंक ऋण में पिछले वर्ष में हुई रु. 19,514 करोड़ की गिरावट की तुलना में रु. 74,238 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण में पिछले वर्ष की रु. 35,799 करोड़ की वृद्धि की तुलना में रु. 2,384 करोड़ की गिरावट हुई। प्राथमिक तौर पर रिजर्व बैंक को निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई 25.7 प्रतिशत की वृद्धि (रु.1,86,985 करोड़) को प्रतिबिंबित करते हुए बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में 28.7 प्रतिशत की वृद्धि (रु.1,93,170 करोड़) हुई।

1.19 रिजर्व बैंक वर्ष के दौरान मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजारों में गहराई और चलनिधि बढ़ाने के लिए उपाय करता रहा। विशेषतः मार्च 2007 में आयी कुछ अस्थिरता सहित 2006-07 के अधिकांश भाग में वित्तीय बाजार आम तौर पर व्यवस्थित बने रहे, जो ऋण की अधिक मांग के साथ व्यापक पूंजी प्रवाह और भारत सरकार के नकदी शेषों में दोलन को प्रतिबिंबित करता है। वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों में ब्याज दरों में रिजर्व बैंक की नीति दर के अनुरूप सख्ती आयी।

1.20 2006-07 के दौरान, वित्तीय बाजार आसान चलनिधि की दशा से सख्ती के आकस्मिक दौरों में परिवर्तित हो गया जिसके कारण एलएएफ के जरिये चलनिधि बढ़ाना जरूरी हो गया। एलएएफ के तहत चलनिधि का कुल ओवरहैंग, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) और केंद्र सरकार की अधिशेष नकदी शेषराशियां कुल मिलाकर मार्च 2006 के रु.74,334 करोड़ के औसत से बढ़कर सितंबर 2006 में रु.92,849 करोड़ हो गयीं। अग्रिम कर अदायगी के कारण मार्च 2007 की दूसरी छमाही में चलनिधि की कमी बढ़ने के कारण 21 मार्च 2007 को एलएएफ के तहत डाली गयी राशि बढ़कर रु. 43,075 करोड़ तक पहुंच गयी। दिसंबर 2006 - मार्च 2007 (विशेष रूप से मार्च 2007 की दूसरी छमाही) में कुछ अवसरों को छोड़कर, जब बाजार में अस्थायी सख्ती आने से एक दिवसीय दरें तेजी से बढ़ीं, एक दिवसीय दरें वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक की रिवर्स रेपो और रेपो दरों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहीं। एक दिवसीय मुद्रा बाजार के संपार्श्विकीकृत खंड में भी ब्याज दरों में तेजी आयी, परंतु वे वर्ष के दौरान मांग दरों के नीचे रहीं। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2006-07 के लिए सीबीएलओ खंड में ब्याज दरों का औसत, मांग मुद्रा बाजार में 7.22 प्रतिशत (5.60 प्रतिशत) की तुलना में क्रमशः 6.24 प्रतिशत (2005-06 में 5.34 प्रतिशत) और बाजार रिपो खंड में 6.34 प्रतिशत (5.36 प्रतिशत) था। मांग मुद्रा, सीबीएलओ और रेपो खंडों में भारित औसत ब्याज दर 2005-06 के 5.43 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 6.57 प्रतिशत हो गयी।

1.21 वाणिज्यिक पत्र पर भारित औसत बट्टा दर 31 मार्च 2006 को समाप्त पखवाड़े के 8.59 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2007 को समाप्त पखवाड़े में 11.33 प्रतिशत हो गयी और जमा प्रमाणपत्रों की भारित औसत बट्टा दर मुद्रा बाजार की अन्य ब्याज दरों में उछाल के अनुरूप मार्च 2006 के अंत के 8.62 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 10.75 प्रतिशत हो गयी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और उधार ब्याज दरें 2006-07 में बढ़ गयीं।

1.22 सरकारी प्रतिभूति बाजार में 2006-07 के दौरान आय बढ़ गयी। वर्तमान वित्त वर्ष में जून 2007 के मध्य तक आय में बढ़त हुई तथा उसके बाद उसमें गिरावट आयी। 31 मार्च 2007 को 10 वर्षीय आय 7.97 प्रतिशत थी जो 31 मार्च 2006 के स्तर (7.52 प्रतिशत) की तुलना में 45 आधार अंक अधिक थी। तथापि आय वक्र चौरस रहा। वर्ष 2007-08 के दौरान मई 2007 के अंत तक आय 7.97 और 8.19 प्रतिशत के दायरे में रही और वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चलते जून 2007 के अंत में यह 8.30 प्रतिशत की ऊंचाई तक पहुंच गई। उसके बाद, चलनिधि की लगातार उपलब्धता को प्रतिबिंबित करते हुए नवंबर 2007 के प्रथम सप्ताह के अंत तक आय में कमी आई और यह 7.85 तथा 8.01 प्रतिशत के बीच रही। 8 नवंबर 2007 को 10 वर्षीय आय 7.96 प्रतिशत थी जो 8 नवंबर 2006 के स्तर से 37 आधार अंक अधिक है।

1.23 वर्ष 2006-07 के दौरान स्टॉक बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गये तथा बीच-बीच में आवधिक सुधार हुआ। पूंजी बाजार के प्राथमिक बाजार खंड में उछाल बना रहा। मार्च 2007 के अंत में बीएसई सेसेक्स एक वर्ष पूर्व के 73.7 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 15.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा। कंपनियों की अधिक लाभप्रदता तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों एवं देशी म्युचुअल फंडों से निरंतर चलनिधि समर्थन के कारण मुद्रा बाजारों में उछाल आया, हालांकि वैश्विक ईक्विटी बाजारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप कुछ अवसरों (मई-जून 2006, दिसंबर 2006 और फरवरी-मार्च 2007) पर उनमें तेज सुधार दिखायी दिया।

1.24 विदेशी मुद्रा बाजार में जुलाई 2006 के मध्य से मजबूती के आग्रह के साथ भारतीय रुपया में 2006-07 में 43.14- 46.97 रुपया प्रति डॉलर के दायरे में घटबढ़ हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और एफआइआइ के बहिर्वाह को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये में शुरुआती मूल्यहास हुआ और वह 19 जुलाई 2006 को 46.97 रुपये पर पहुंच गया। तथापि, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, बड़ी मात्रा में पूंजी आवकों तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमरीकी डॉलर की कमजोरी के कारण रुपये में उसके बाद तेजी आयी और वह 28 मार्च 2007 को रु. 43.14 प्रति अमरीकी डॉलर तक आ गया। मार्च 2007 के अंत में विनिमय दर रु. 43.60 प्रति डॉलर थी।

1.25 अच्छे समष्टि आर्थिक मूलतत्वों को दर्शाते हुए, 2006-07 के दौरान बाह्य क्षेत्र में भारत के भुगतान शेष की स्थिति में लगातार सुदृढ़ता और सक्रियता आयी। पण्य निर्यात और तेलेतर आयात वृद्धि में सामान्य बढ़त बनी रही, जबकि पिछले

वर्ष इनमें सुदृढ़ वृद्धि देखी गई थी। साफ्टवेयर निर्यात एवं अन्य कारोबारी सेवाओं से प्राप्त आय तथा विदेश में कार्यरत भारतीयों से प्राप्त अर्थप्रेषण में उछाल बना रहा। 2006-07 के दौरान अदृश्य मदों के तहत निवल अधिदेश बढ़ा तथा उसने बढ़ते हुए पण्य व्यापार घाटे के बड़े भाग का वित्तपोषण करना जारी रखा। फलस्वरूप, वर्ष के दौरान चालू खाता घाटा कम बना रहा और जीडीपी के अनुपात के रूप में एक वर्ष पूर्व के स्तर पर (1.1 प्रतिशत) था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की अगुआई में भारत में पूंजी प्रवाह में 2006-07 के दौरान बड़ी वृद्धि हुई, जो वृद्धि की संभावना की सुदृढ़ता और देशी निवेश और आयात मांग में उछाल द्वारा समर्थित थी। बाहरी प्रत्यक्ष निवेश में भी उछाल आया जो भारतीय कंपनियों द्वारा बढ़ते हुए विदेशी अर्जन को दर्शाता है। निवल पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटा से अधिक होने के साथ, समग्र भुगतान शेष में उल्लेखनीय अधिशेष दर्ज हुआ जो 2006-07 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 47.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि में दिखायी दिया। जहां उच्चतर बाह्य वाणिज्यिक उधारों एवं अनिवासी जमाराशियों के कारण बाह्य ऋण के स्टॉक में वृद्धि हुई, वहीं विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में लगातार वृद्धि को दर्शाते हुए निवल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में गिरावट आयी, जो मार्च 2007 के अंत तक बढ़कर 199.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गयी।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1.26 बैंकिंग क्षेत्र ने 2006-07 के दौरान तीव्र वृद्धि दर्ज की। वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र की तीव्र वृद्धि ने मार्च 2007 के अंत में जीडीपी के प्रति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों के अनुपात को बढ़ाकर 92.5 प्रतिशत कर दिया। वर्ष के दौरान आवास और वाणिज्यिक वास्तविक संपदा क्षेत्र से हटकर क्षेत्रीय ऋण आबंटन में कुछ पुनः संतुलन के साथ व्यापक ऋण वृद्धि आधार देखा गया। तथापि, मुख्यतः मीयादी जमाराशियों में तीव्र वृद्धि के कारण जमाराशियों में तेज वृद्धि ने बैंकों द्वारा ऋण वृद्धि को वित्तपोषित करने हेतु निवेश संविभाग को खोलने की जरूरत को समाप्त कर दिया जैसाकि पिछले वर्ष देखा गया था (सारणी I.1)। तथापि, कुल आस्तियों और निवल मांग और मीयादी देयताओं दोनों के प्रतिशत के रूप में बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश गिरावट जारी रही। निजी क्षेत्र के तीन पुराने बैंकों के विलय के साथ बैंकिंग क्षेत्र का समेकन जारी रहा जिससे अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या मार्च 2006 के अंत में 85 से घटकर 82 रह गयी।

सारणी 1.1: वित्तीय क्षेत्र के चुनिंदा संकेतक : 2006-07

श्रेणी	संकेतक	2005-06	2006-07
1	2	3	4
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	क) प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)		
	सकल जमाराशियां	17.8	24.6
	ऋण और अग्रिम	31.8	30.6
	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	-1.2	9.3
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	परिचालनगत लाभ	2.0	1.9
	निवल लाभ	0.9	0.9
विस्तार	2.8	2.7	
ग) अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)			
सकल अनर्जक आस्तियां	3.1	2.4	
निवल अनर्जक आस्तियां	1.2	1.0	
2. शहरी सहकारी बैंक	क) प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)		
	जमाराशियां	6.3	6.1
	ऋण	4.0	9.8
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)@		
	परिचालनगत लाभ	1.3	1.2
	निवल लाभ	0.8	0.6
	विस्तार	2.2	2.3
ग) अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)			
सकल अनर्जक आस्तियां	18.9	17.0	
निवल अनर्जक आस्तियां	8.8	7.7	
3. ग्रामीण सहकारी बैंक	क) संख्या	1,07,497	-
	ख) प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)		
	जमाराशियां	4.9	-
	ऋण	6.2	-
	ग) वित्तीय संकेतक		
	लाभ अर्जक सोसाइटियां (संख्या)	44,968	-
	घाटे में चल रही सोसाइटियां (संख्या)	53,344	-
कुल लाभ / हानि (करोड़ रुपए)	-271	-	
घ) अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)*	23.8	-	
4. वित्तीय संस्थाएँ	क) प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत) ¹		
	मंजूरी	41.0	12.9
	संवितरण	47.1	82.8
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) ²		
	परिचालनगत लाभ	1.4	2.1
	निवल लाभ	1.0	1.5
	विस्तार	1.8	1.6
5. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	क) प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)		
	जनता की जमाराशियां	-32.1	-16.5
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	निवल लाभ	1.5	1.2
	ग) अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में) ³		
	निवल अनर्जक आस्तियां	0.5	0.4
	6. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां	क) प्रमुख समुच्चय में वृद्धि (प्रतिशत)	
जमाराशियां		21.5	12.1
ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)			
निवल लाभ		0.7	0.9

- : उपलब्ध नहीं

@ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित हैं।

* प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बकाया राशियां शामिल हैं।

1 आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, सिडबी, आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ वेंचर, टीएफसीआइ, एलआइसी और जीआइसी से संबंधित हैं।

2 सात वित्तीय संस्थाओं नामतः आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, एक्जिम बैंक, टीएफसीआइ, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी से संबंधित हैं।

3 रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों के लिए, व्याप्त में अंतर के साथ।

1.27 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन, देयताओं और आस्तियों दोनों पक्षों में, ब्याज दरों की सख्ती से समर्थित था। बैंकों की निवल ब्याज आय और ब्याजेतर आय दोनों कुल रूप में तेजी से बढ़ी परंतु कुल आस्तियों की तुलना में उसमें गिरावट आयी। तथापि, बैंक परिचालन व्यय को कम करके लाभप्रदता बनाये रखने में सफल रहे। पिछले वर्ष से भिन्न, बैंकों द्वारा किये गये प्रावधान और आकस्मिक व्यय वर्ष के दौरान बढ़ गये हालांकि वे सापेक्षिक रूप में (अर्थात् आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) थोड़े कम थे। जहां अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का आस्तियों पर प्रतिलाभ स्थिर रहा, वहीं ईक्विटी पर उनके प्रतिलाभ में वर्ष के दौरान सुधार आया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभ में तेज वृद्धि हुई, जिसे ऋण की मात्रा में सुदृढ़ वृद्धि और परिचालनात्मक व्ययों में नियंत्रण के कारण निवल ब्याज आय में तीव्र वृद्धि से सहारा मिला।

1.28 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में 2006-07 के दौरान सुधार आया, जो ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल और निवल अनर्जक आस्तियों में गिरावट के रूप में प्रतिबिंबित हुआ। तथापि, सकल अनर्जक आस्तियों में बैंक समूहों के बीच अलग-अलग प्रवृत्ति थी। जहां वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (विशेषतः राष्ट्रीकृत बैंकों) और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की कुल सकल अनर्जक आस्तियों में गिरावट आयी, वहीं निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में उसमें वृद्धि हुई।

1.29 पूंजी जुटाने के बैंकों के प्रयास, आस्तियों में वृद्धि तथा नयी आस्तियों के जोखिम की रूपरेखा के अनुरूप थे। अतः अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जोखिम भारित पूंजी अनुपात, जो हानि को सहने संबंधी बैंकिंग प्रणाली की क्षमता की माप है, मार्च 2006 के अंत के अनुरूप मार्च 2007 के अंत में 12.3 प्रतिशत पर था।

सहकारी बैंक

1.30 शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन में 2006-07 के दौरान सामान्य वृद्धि हुई। जमाराशियों में वृद्धि की तुलना में ऋण और अग्रिमों में उच्चतर वृद्धि देखी गयी। यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के लक्ष्य में चूक की, परंतु उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित उप-लक्ष्य पूरे कर लिये। मुख्यतः एसएलआर निवेशों में गिरावट के कारण वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के निवेश में गिरावट आयी, तथापि, एसएलआर से इतर निवेश में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन में उच्चतर परिचालन और शुद्ध लाभ तथा ब्याज-अंतराल में वृद्धि के साथ उल्लेखनीय

सुधार हुआ। यह विजन दस्तावेज द्वारा सुझायी गयी मध्यावधि रूपरेखा की सफलता की ओर संकेत करता है। कुल और सापेक्ष दोनों रूपों में सकल और निवल अनर्जक आस्ति में गिरावट के साथ, शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

1.31 वर्ष 2005-06 के दौरान, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को छोड़कर ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सभी खंडों के तुलनपत्र 2005-06 में बढ़ गये। तथापि, वर्ष के दौरान उनके वित्तीय कार्य-निष्पादन में गिरावट आयी। ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न खंडों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में व्यापक घट-बढ़ देखा गया। जहां 2005-06 के दौरान अल्पावधि और दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं दोनों के ऊपरी स्तर ने लाभ कमाया, वहीं निचले स्तर (अर्थात् पीएसीएस और पीसीएआरडीबी) ने समग्र रूप से हानि उठायी। सुधरे हुए वसूली कार्य-निष्पादन वाली प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को छोड़कर सभी प्रकार के ग्रामीण सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आयी। वर्ष के दौरान डीसीसीबी और पीसीएआरडीबी का वसूली कार्यनिष्पादन खराब हुआ।

वित्तीय संस्थाएं

1.32 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता में, उनके द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता में गिरावट के बावजूद, 2006-07 में तेज वृद्धि हुई। 2006-07 में वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष के दौरान देखी गयी क्रमशः 41.0 प्रतिशत तथा 38.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में क्रमशः 12.9 प्रतिशत और 82.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मुख्यतः निवेश संस्थाओं और विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरण में वृद्धि के कारण संवितरणों में तेज वृद्धि हुई, जबकि अखिल भारतीय मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा कम स्वीकृति के कारण स्वीकृतियों में कमी आयी।

1.33 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शुद्ध ब्याज आय में, 2005-06 के 20.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 2006-07 में 1.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं की ब्याजेतर आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तथापि, पिछले वर्ष की तीव्र वृद्धि के विपरीत वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं के परिचालनागत व्यय में 55.9 प्रतिशत की गिरावट आयी। फलस्वरूप, वर्ष के दौरान परिचालनात्मक लाभ में 73.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई। यह कराधान के लिए चिह्नित उच्चतर प्रावधानों के बावजूद वित्तीय संस्थाओं के निवल लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में भी प्रतिबिंबित हुआ। वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक बना रहा।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1.34 वर्ष 2005-06 में 5.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की तुलना में जमाराशि लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति/देयता में वर्ष 2006-07 में 26.9 प्रतिशत की काफी तीव्र वृद्धि हुई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी की उधारी, जोकि उनकी निधियों का प्रमुख स्रोत है, में वर्ष के दौरान 30.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि जमाराशि में 16.5 प्रतिशत की गिरावट आई। निधि आधारित आय में तीव्र वृद्धि के चलते 2006-07 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-डी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का चेहरा ही बदल गया जिसने परिचालन व्यय और वित्तीय व्यय में हुई तीव्र वृद्धि के असर को कम किया। परिणामस्वरूप, परिचालन लाभ और निवल लाभ दोनों में वृद्धि हुई। आस्ति की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ। वर्ष के दौरान जहां 30 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर वाली एनबीएफसी-डी के अनुपात में कमी आई वहीं 12 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाली एनबीएफसी-डी के अनुपात में भी यही रुख रहा। एनबीएफसी समूह में सकल आस्ति / देयता में सबसे बड़ा हिस्सा आस्ति वित्त कंपनियों का (51.5 प्रतिशत) था उसके बाद किराया खरीद वित्त कंपनियों (35.7 प्रतिशत), ऋण कंपनियों (8.7 प्रतिशत) तथा निवेश कंपनियों (3.4 प्रतिशत) का था।

1.35 100 करोड़ रुपए और इससे अधिक की आस्ति आकार वाली जमा राशि न लेनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण 173 एनबीएफसी से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के अंत में उनकी आस्ति / देयता में वर्ष 2006 की तुलना में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की कुल उधारी 26.8 प्रतिशत बढ़कर 2,11,986 करोड़ रुपए हो गई जोकि कुल देयताओं का 66.7 प्रतिशत है। मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआइ ने 7,460 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जोकि मार्च 2006 समाप्त वर्ष के दौरान अर्जित लाभ (4,301 करोड़ रुपए) की तुलना में 73.4 प्रतिशत अधिक है जो अंशतः यह दर्शाता है कि इस श्रेणी में कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

2007-08 के दौरान हुई गतिविधियां

1.36 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अगस्त 2007 में दिये गये अनुमान के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च दर पर वृद्धि जारी रही और 2006-07 की पहली तिमाही में हुई 9.6 प्रतिशत की

वास्तविक जीडीपी वृद्धि की तुलना में 2007-08 की पहली तिमाही में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वास्तविक जीडीपी में हुई वृद्धि को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में द्वि-अंकीय वृद्धि से समर्थन मिला जबकि कृषि क्षेत्र में सुधार के संकेत दिखायी दिये।

1.37 थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़ द्वारा मापी गयी मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मार्च 2007 के अंत के 5.9 प्रतिशत से कम होकर 27 अक्टूबर 2007 को 3.0 प्रतिशत हो गयी। सभी प्रमुख समूहों, प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन समूह और विनिर्माण उत्पादों के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर मार्च 2007 के अंत में क्रमशः 10.7 प्रतिशत, 1.0 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत थी जो 27 अक्टूबर 2007 को कम होकर क्रमशः 5.1 प्रतिशत, -1.5 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत रह गयी। राजकोषीय और आपूर्ति पक्ष के उपायों सहित 2004 के मध्य से पूर्वोपाय के रूप में किये गये मौद्रिक उपायों ने मुद्रास्फ़ीतिकारी दबावों को रोकने में मदद की। 2007-08 की दूसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में तेजी बनी रही तथा वह थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के ऊपर बनी रही जो मुख्यतः उच्चतर खाद्य मूल्यों के प्रभाव को दर्शाता है।

1.38 2007-08 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त के प्रमुख घाटा संकेतकों में कुल तथा जीडीपी के अनुपात दोनों रूपों में 2006-07 के संशोधित अनुमानों में गिरावट आने का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के राजस्व खाता में अधिशेष राजकोषीय पक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। राजस्व खाते में परिकल्पित सुधार से संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा में 2007-08 में जीडीपी के 0.8 प्रतिशत की कमी आने की आशा है। 2007-08 (अप्रैल - सितंबर 2007) के पहले छह माह लिए केंद्र सरकार के वित्त के बारे में उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि बजट अनुमान की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा (रिजर्व बैंक को भारतीय स्टेट बैंक के अंश के अर्जन की लागत और रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को अंतरित लाभ के अंतर की राशि) अप्रैल-सितंबर 2006² की तुलना में कम स्तर पर रखा गया है। अप्रैल-सितंबर 2007 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम था। तथापि, राजस्व घाटे के लिए कम राशि बजट किए जाने के कारण 22.6 प्रतिशत अधिक की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के बावजूद बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में यह राशि पिछले वर्ष से सामान्य अधिक थी।

1.39 राजकोषीय वर्ष 2007-08 में (26 अक्टूबर 2007 तक), पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की 7.9 प्रतिशत की वृद्धि की

² भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के अंश के अंतरण के कारण अधिशेष अंतरण की राशि (34,308 करोड़ रुपए) अप्रैल-अगस्त 2007 के लिए गैर-कर राजस्व के अंतर्गत शामिल किया गया था। जैसा कि केंद्र सरकार के 2007-08 के बजट में उल्लेख किया गया है, लेखा महानियंत्रक द्वारा इस लेनदेन को अप्रैल-सितंबर 2007-08 के लिए गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत रिकार्ड किया गया है।

तुलना में एम₃ में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। साल-दर-साल आधार पर एक वर्ष पूर्व के 18.4 प्रतिशत की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार एम₃ में वृद्धि वार्षिक नीति विवरण (अप्रैल 2007) में 2007-08 के लिए निर्धारित 17.0 -17.5 प्रतिशत के संकेतात्मक दायरे से अधिक बनी रही। सरकार को निवल बैंक ऋण में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में हुई 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष (26 अक्टूबर 2007 तक) में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 9.0 प्रतिशत की तुलना में 5.1 प्रतिशत बढ़ा। सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में वाणिज्य बैंकों का निवेश उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के प्रतिशत के रूप में, मार्च 2007 के अंत के 28.0 प्रतिशत से बढ़कर 14 सितंबर 2007 को 29.4 प्रतिशत हो गया। आरक्षित मुद्रा में एक वर्ष पूर्व के 15.6 प्रतिशत की तुलना में 2 नवंबर 2007 को साल-दर-साल 26.7 प्रतिशत (सीआरआर में वृद्धि के पहले दौर के प्रभावों के लिए 17.1 प्रतिशत पर समायोजित) की वृद्धि हुई। सीआरआर में वृद्धि के कारण अप्रैल 2007 के मध्य से चलनिधि का दबाव बढ़ा परंतु 28 मई 2007 से उसमें क्रमिक रूप से नरमी आयी जो सरकारी खर्च में वृद्धि तथा रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों से विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद को दर्शाता है। 2007-08 की दूसरी तिमाही में (सितंबर के मध्य तक) रिजर्व बैंक ने एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो का उपयोग करते हुए चलनिधि को अवशोषित करना जारी रखा।

1.40 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खाद्येतर ऋण में मार्च 2007 के अंत के 28.4 प्रतिशत और एक वर्ष पूर्व के 29.7 प्रतिशत की तुलना में 26 अक्टूबर 2007 को साल-दर-साल 23.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जमाराशियों में वृद्धि में तेजी के साथ ऋण वृद्धि में कमी के फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात (साल-दर-साल) पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 98.3 प्रतिशत की तुलना में 14 सितंबर 2007 को कम होकर 62.9 प्रतिशत रह गया। 17 अगस्त 2007 तक उपलब्ध क्षेत्रवार नियोजन आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वृद्धिशील खाद्येतर ऋण (साल-दर-साल) का 41 प्रतिशत उद्योग द्वारा, लगभग 13 प्रतिशत कृषि द्वारा और लगभग 22 प्रतिशत व्यक्तिगत ऋण द्वारा अवशोषित किया गया। उद्योग क्षेत्र में, ऋण की मांग निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, (पावर, पत्तन, दूरसंचार आदि), वस्त्र, लोहा एवं इस्पात, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, खाद्य अभिसंस्करण, रसायन, वाहन और निर्माण उद्योगों द्वारा की गयी। उद्योग को दिये गये वृद्धिशील ऋण का 27 प्रतिशत से अधिक केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में गया। वाणिज्यिक वास्तविक संपदा को ऋण में वृद्धि उच्च स्तर पर रही।

1.41 अब तक 2007-08 के दौरान भारतीय वित्तीय बाजार आम तौर पर व्यवस्थित बना रहा। अप्रैल-जुलाई 2007 के दौरान मांग मुद्रा दरों में नरमी की प्रवृत्ति के फलस्वरूप, वे जून-जुलाई 2007 के बीच रिवर्स रेपो दर के नीचे रहे। तथापि, 6 अगस्त 2007 से दैनिक रिवर्स रेपो पर रु.3000/- करोड़ की उच्चतम सीमा हटाने के फलस्वरूप, मांग मुद्रा दरों में तेजी आयी। सितंबर 2007 के दौरान, मांग मुद्रा दरें कमोबेश रिवर्स रेपो और रिपो दर द्वारा निर्धारित अनौपचारिक सीमा के भीतर रहीं। 15 अक्टूबर 2007 को वाणिज्यिक पत्रों का निर्गम मार्च 2007 के अंत के रु. 17,688 करोड़ से बढ़कर रु. 38,495 करोड़ हो गया। वाणिज्यिक पत्र पर भारित औसत बढ़ा दर जून 2007 के अंत के 8.93 प्रतिशत से घटकर 15 अक्टूबर 2007 को 7.99 प्रतिशत हो गयी और वाणिज्यिक पत्र की अधिक तरजीह वाली परिपक्वता '61 से 90 दिन' और '181 दिन और अधिक' के बीच रही। पट्टादायी और वित्तीय कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक पत्रों का बड़ी मात्रा में जारी करना बना रहा। जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि मार्च 2007 के अंत के रु.93,272 करोड़ (4.8 प्रतिशत) से बढ़कर 28 सितंबर 2007 को रु.1,18,481 करोड़ (जारीकर्ता बैंकों की कुल जमाराशियों का 5.55 प्रतिशत) हो गयी। जमा प्रमाणपत्रों पर भारित औसत बढ़ा दर मार्च 2007 के अंत के 10.75 प्रतिशत की तुलना में 28 सितंबर 2007 को गिरकर 8.57 प्रतिशत रह गयी।

1.42 मुद्रास्फीति में आ रही नरमी और मुद्रा बाजार खंड की प्रवृत्तियों के अनुरूप 91-दिवसीय खजाना बिलों पर प्राथमिक आय मार्च 2007 के 7.73 प्रतिशत से गिरकर अक्टूबर 2007 में 7.11 प्रतिशत हो गयी। 364 दिवसीय और 91 दिवसीय खजाना बिलों के बीच आय अंतराल मार्च 2007 के 23 आधार अंकों से बढ़कर अक्टूबर 2007 में 26 आधार अंक हो गया। 8 नवंबर 2007 को 10 वर्षीय आय, मार्च 2007 के अंत की आय (7.97) की तुलना में 7.96 प्रतिशत पर लगभग अपरिवर्तित रही। 1-10 वर्ष की आय के बीच का अंतराल मार्च 2007 के अंत के 42 आधार अंकों से सिमटकर अक्टूबर 2007 के अंत में 21 आधार अंक हो गया।

1.43 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा दरें, विशेषतः विभिन्न परिपक्वताओं के दायरे के ऊपरी छोर पर जुलाई 2007 और अगस्त 2007 के बीच गिर गयी। एक से तीन साल की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ब्याज दरें जून 2007 के 7.25 - 9.75 प्रतिशत (मार्च 2007 में 7.25 - 9.50 प्रतिशत) की तुलना में अगस्त 2007 में 7.25-9.00 प्रतिशत के दायरे में थीं, जबकि तीन साल से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर वे जून 2007 के 7.75 - 9.75 प्रतिशत की तुलना में (मार्च 2007 में 7.50 - 9.50 प्रतिशत) अगस्त 2007 में 7.75 - 9.50 प्रतिशत

के दायरे में थीं। 2007-08 की दूसरी तिमाही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का बीपीएलआर अपरिवर्तित रहा, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में वह जून 2007 के 13.00-17.25 प्रतिशत की तुलना में अगस्त 2007 में नरम होकर 13.00-16.50 प्रतिशत के दायरे में आ गया।

1.44 2007-08 के दौरान, भारतीय रुपया ने दूसरी तिमाही के दौरान घट-बढ़ दर्शाया जबकि मई 2007 के अंत तक उसमें अमरीकी डॉलर की तुलना में वृद्धि हुई थी। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान (8 नवंबर 2007 तक) रुपया 39.26 - 43.15 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर के दायरे में रहा। 2007-08 के दौरान अब तक (8 नवंबर 2007 तक) भारतीय रुपए में अमरीकी डॉलर की तुलना में 10.8 प्रतिशत, पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में 3.6 प्रतिशत, यूरो की तुलना में 1.0 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई।

1.45 वर्ष 2007-08 के दौरान तेजी के रुख को जारी रखते हुए सेंसेक्स 2 नवंबर 2007 को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ जो कि मार्च 2007 के अंत की स्थिति से 52.82 प्रतिशत अधिक है। 2 नवंबर 2007 को एसएंडपी और निफ्टी भी 5932 के रिकार्ड स्तर तक पहुंचा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू स्टॉक मार्केट में जिन क्षेत्रों के स्टॉक में वृद्धि हुई उनमें पूंजीगत वस्तुएं, धातु, तेल तथा गैस, उपभोक्त वस्तुएं तथा बैंकिंग क्षेत्र शामिल है। बाजार में तेजी के रुझान को हवा देने में इन कारकों की भूमिका रही - विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आइ आइ), द्वारा चलनिधि समर्थन, जीडीपी में सुदृढ़ वृद्धि, कंपनियों की लाभप्रदता में भारी वृद्धि, घरेलू मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में कमी, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ईक्विटी बाजारों का

उर्ध्वगामी रुख, तथा धातुओं की कीमतों में वृद्धि। तथापि, यूएस तथा यूरोप में सब-प्राइम हानियों तथा ऋण में अत्यधिक तंगी एवं प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के अवमूल्यन के चलते प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ईक्विटी बाजारों में गिरावट आई जिसके कारण घरेलू स्टॉक बाजार में 2 नवंबर 2007 के बाद कुछ करेक्शन हुए। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में रिकार्ड वृद्धि, एफआईआई द्वारा भारतीय ईक्विटी बाजार में निवल बिक्री, डॉलर की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर धातुओं की कीमतों में गिरावट तथा अन्य क्षेत्र तथा स्टॉक विशेष से संबंधित सूचनाओं ने बाजार के रुख को नरम करने का काम किया।

1.46 2007-08 के दौरान अब तक भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति सुखद बनी रही। जहां पण्य निर्यात में अप्रैल-जुलाई 2007 के दौरान कुछ कमी आयी वहीं उसी अवधि में आयात में समग्र वृद्धि उंची रही। तथापि, तेल आयात में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान दर्ज सुदृढ़ वृद्धि की तुलना में तीव्र कमी आयी। निजी अंतरणों में उच्चतर वृद्धि की अगुआई में 2007-08 की पहली तिमाही में अदृश्य खातों में अधिशेष ने 2007-08 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा को कम करके 4.7 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया। पोर्टफोलियो निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार के तहत बड़े प्रवाहों को दर्शाते हुए, निवल पूंजी आवक 2006-07 की पहली तिमाही के 10.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2007-08 की तदनु रूप अवधि में बढ़कर 15.3 बिलियन अमरीकी डॉलर पर काफी अधिक था। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां मार्च 2007 के अंत के 199.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से और बढ़कर 21 सितंबर 2007 को 236 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गयी।